(ग) वर्ष 1982-83 के अन्त तक अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता 3.20 लाख मी० टन तक हो जाने की आशा है । नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स (75000 मी० टन वार्षिक क्षमता) नामक विद्यमान एकक के अलावा हिन्दुस्तान पेपर निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही केरल न्यूजप्रिंट परियोजना (80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता) के द्वारा 1979 के अन्त तक वाणिज्यिक उत्पादन होने लगने की आशा है तथा मैसूर पेपर मिल्स (कर्नाटक) द्वारा क्रियान्वित की जा रही अखबारी कागज परियोजना (75,000 मी० टन वार्षिक क्षमता) के वर्ष 1980-81 में शुरू हो जाने की आशा है ।

शीतल पेयों की बिक्री के आंकड़े

4121. श्री भोविन्द मुण्डा : क्या उद्योग मंत्री "थम्स-अप" और '77" पेय की बिक्री के बारे में 13 दिसम्बर, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रांड नामों से बेचे गए विभिन्न शीतल पेयों के बारे में बिक्री के आंकड़े न रखने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में मैसर्स पार्ले बेवरेजेस लिमिटेड बम्बई आदि जैसी कम्पनियों के बारे में इस प्रकार के आंकड़े रखने का ; है और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी अपने पास पंजीयित एककों के बारे में वस्तुवार उत्पादन के आंकड़े रखते हैं । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एकत्रित करने अथवा इस उद्योग में उत्पादन विनियमित करने के उद्देश्य से शीत-पेय के बिक्री आगम विषयक ब्रांड-वार आंकड़े संगत नहीं समझे जाते हैं ।

रुई की गांठों का निर्यात

4122. श्री छीदू भाई पामित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रूई निगम पहले आयातित रूई की एक लाख से अधिक गांठों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को घाटा होने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या वर्ष, 1977 में कपड़ा मिलों के लिये निगम द्वारा आयातित रूई की कुल मात्रा में से एक लाख रूई की गांठें अभी बिना बिकी पड़ी हुई हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती आभा माथुर) : (क) भारतीय रूई निगम को पहले आयात की गई रूई की कुछ मात्रा का निर्यात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) चूंकि प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः इस अवस्था में हानि और लाभ की सम्भाव्यता निश्चित नहीं की जा सकती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मांग करने वाली कुछ पार्टियां इस आधार पर अपने दायित्वों से पीछे हट गई क्योंकि आयातित रूई के भारत में पहुचने के समय तक घरेलू मूल्य स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति आ गई थी जिससे आयातित रूई के मूल्य उद्योग के हितों के प्रतिकूल हो चले थे ।

Per Capita Income in J & K

4123. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state the per capita income in the Jammu and Kashmir State separately for Jammu, Srinagar and Ladakh regions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI FAZLUR RAHMAN): Separate estimates of per capita income of Jammu, Srinagar and Ladakh regions are not available. According to estimates released by the State Directorate of Evaluation and Statistics per capita income of Jammu and Kashmir for 1976-77 is Rs. 897 at current prices.

Population living below the Poverty Line

4124. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the present percentage of population living below the poverty line;